दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

अर्द्ध-वार्षिकी 2020

पिछले छः माह के करेंट अफेयर्स पर बिंदुवार पुनरावलोकन

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

(यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर केंद्रित)

1

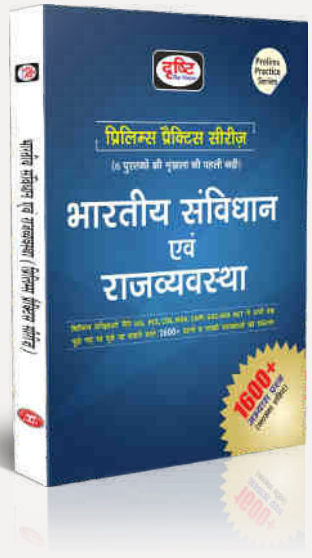

2

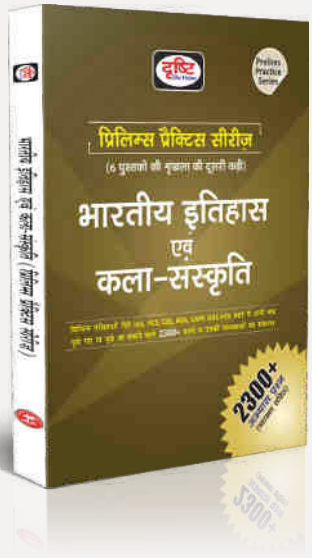

3

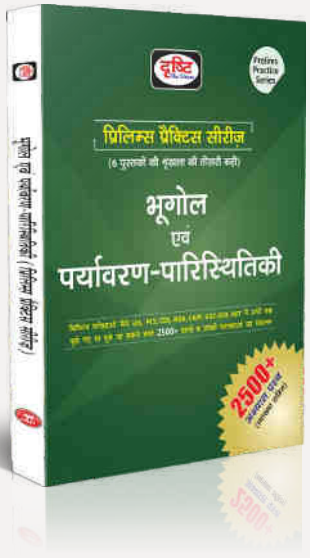

4

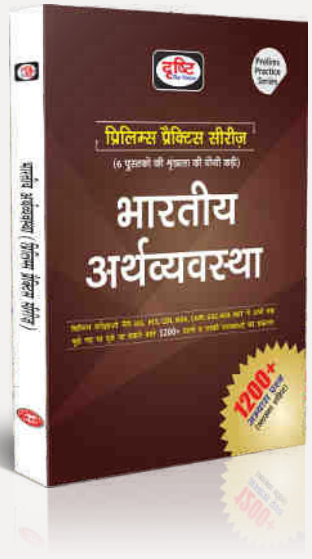

5

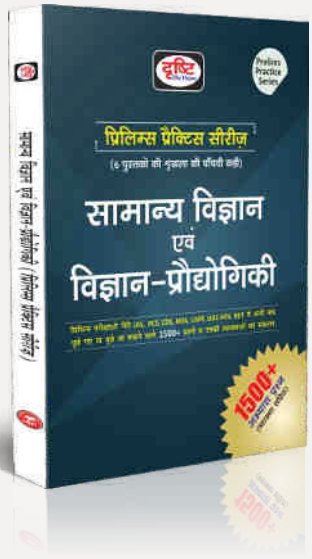

6

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

अर्द्ध-वार्षिकी 2020

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 87501 87501, 011-47532596

Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
booksteam@groupdrishti.com

संस्करण- अगस्त 2020

मूल्य : ₹ 150

प्रकाशक

(A Unit of VDK Eduventures Pvt. Ltd.)

641, प्रथम तल,

डॉ. मुखर्जी नगर,

दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं होगा।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है, तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Eduventures Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हम करेंट अफेयर्स पर आधारित 'वार्षिकी' का प्रकाशन करते आए हैं। इसमें हम विगत एक वर्ष के सभी परीक्षोपयोगी समसामयिक घटनाक्रम का संकलन प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक की उपयोगिता को लेकर इतने सकारात्मक संदेश आए कि हमारा उत्साह भी बढ़ा और हम कुछ नए प्रयोगों को अपनाने के लिये भी आगे आ पाए। इसी कड़ी में अब हम आपके लिये लेकर आ रहे हैं 'अर्द्धवार्षिकी'। इसमें हमने विगत 6 महीने की तमाम महत्त्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया है। ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि आप पर करेंट अफेयर्स को तैयार करने का इकट्ठा भार न पड़े। आप आधे हिस्से को अभी तैयार कर लें और जब 'वार्षिकी' आए तो आपकी तैयारी भी पूरी हो जाए और एक हिस्सा अपने आप ही रिवाइज़ भी हो जाए। साथ ही इससे आपको मध्य में आने वाली अनेक परीक्षाओं में मदद भी मिल सके।

गौरतलब है कि आई.ए.एस., पी.सी.एस. सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 'करेंट अफेयर्स' का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस खंड की ठोस तैयारी के बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्तमान में करेंट अफेयर्स से संबंधित ढेर सारी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं, किंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से एक भी पुस्तक परीक्षा की बदलती प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं है। इन पुस्तकों में तथ्यात्मक अशुद्धियों के साथ-साथ गैर-परीक्षोपयोगी तथ्यों की भी भरमार है। अद्यतनता के अभाव एवं पुरानी घटनाओं के बार-बार दुहराव के कारण ये पुस्तकें अनुपयोगी तथ्यों का भंडारमात्र बन कर रह गई हैं जो विद्यार्थियों को तैयारी के दौरान दिग्भ्रमित कर देती हैं।

अभी आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा की चुनौती है। क्योंकि आई.ए.एस. सहित कई राज्यों की पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षाएँ होने वाली हैं। 'अर्द्धवार्षिकी' इन चुनौतियों से पार पाने में आपके लिये प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी। हालाँकि यह पुस्तक मुख्यत: करेंट अफेयर्स की हमारी मासिक पत्रिका 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पिछले 6 महीने के अंकों के आधार पर संकलित है, फिर भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, साइंस रिपोर्टर, योजना, कुरुक्षेत्र आदि पत्र-पत्रिकाओं सहित कुछ वेबसाइट्स आदि से भी परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीयों को इस पुस्तक में संलग्न कर इसे नवीनता और समग्रता प्रदान की गई है। इससे निश्चय ही दृष्टि की मासिक पत्रिका के नियमित पाठकों को भी नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। यद्यपि 6 माह के करेंट अफेयर्स के विशाल भंडार से परीक्षोपयोगी तथ्यों को मात्र 184 पृष्ठों में प्रस्तुत करना सागर से मोती चुनने जैसा कार्य था, तथापि हमारी अनुभवी और दक्ष टीम ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

11 खंडों में विभाजित इस पुस्तक का प्रत्येक खंड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप तैयार किया गया है। पुस्तक को त्रुटिहीन तथा अद्यतन बनाने के लिये इसका कई चरणों में सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। विद्यार्थियों को पढ़ते समय तथ्यों की दुरूहता की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिये उनका बिंदुवार प्रस्तुतीकरण किया गया है। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं पर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है, अत: हमने इसमें 'सरकारी योजनाएँ' नाम से भी एक खंड रखा है। इसमें नई योजनाओं के साथ-साथ पहले से चल रही योजनाओं को भी शामिल किया गया है। विविध और खेल घटनाक्रम को नए और रोचक अंदाज़ में प्रस्तुत किया गया है जिससे अभ्यर्थियों को तथ्यों को आत्मसात् करने में आसानी होगी।

हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी तैयारी एवं सफलता में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आपसे निवेदन है कि आप इस पुस्तक को एक पाठक के साथ-साथ आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। **अगर आपको कोई भी इसमें कमी दिखे, तो आप बेझिझक अपने सुझाव हमें 8130392355 नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज सकते हैं।** आपकी टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर ही हम पुस्तक को और बेहतर व प्रामाणिक बना सकेंगे।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1. संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम 1-31

2. आर्थिक घटनाक्रम 32-61

3. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 62-84

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 85-103

5. भूगोल, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन 104-123

6. सुरक्षा 124-133

7. रिपोर्ट एवं सूचकांक 134-141

8. सरकारी योजनाएँ 142-150

9. कला एवं संस्कृति 151-161

10. खेल घटनाक्रम 162-171

11. विविध 172-180

1 संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम (Constitutional and Administrative Events)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' (National Education Policy–2020) को मंज़ूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' [National Policy on Education (NPE), 1986] को प्रतिस्थापित करेगी।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था।
- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020' वर्ष 1968 और वर्ष 1986 (जिसे 1992 में संशोधित किया गया था) के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।
- NEP-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।
- तकनीकी शिक्षा, भाषायी बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
- इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

MHRD के नाम में परिवर्तन

- कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development–MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Ministry of Education) करने को भी मंज़ूरी दी गई है।
- NEP-2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने का उद्देश्य 'शिक्षा और सीखने (Education and Learning)' पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है।

प्रारंभिक शिक्षा

- एनसीईआरटी द्वारा 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये दो भागों में प्रारंभिक वाल्यावस्था शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा अर्थात् 0-3 वर्ष के बच्चों के लिये सब-फ्रेमवर्क और 3-8 वर्ष के लिये एक अन्य सब-फ्रेमवर्क-
  - 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री-स्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (Early Childhood Care and Education–ECCE) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 और कक्षा-2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा।

'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन'

- NEP-2020 में MHRD द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना की मांग की गई है।
- राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

भाषायी विविधता को बढ़ावा और संरक्षण

- NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र-छात्रा पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

2 आर्थिक घटनाक्रम (Economic Events)

एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा 'विश्व बैंक' (World Bank) के साथ 'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' (MSME Emergency Response Programme) के लिये **750 मिलियन डॉलर के समझौते** पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य COVID-19 महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित **'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों' (Micro, Small, and Medium Enterprises–MSMEs) में वित्त का प्रवाह** बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1.5 मिलियन MSMEs की नकदी एवं ऋण संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा ताकि मौजूदा प्रभावों को कम करने के साथ-साथ लाखों नौकरियों को सुरक्षित किया जा सके।
- विश्व बैंक की ऋण प्रदान करने वाली शाखा 'अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक' (International Bank for Reconstruction and Development–IBRD) से मिलने वाले 750 मिलियन डॉलर के इस **ऋण की परिपक्वता अवधि 19 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल** है।
- COVID-19 महामारी से MSME क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है जिसके चलते यह क्षेत्र आजीविका एवं रोज़गार दोनों ही मोर्चों पर व्यापक नुकसान उठा रहा है।
- भारत सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करने पर है कि वित्तीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरलता का प्रवाह 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' की तरफ बना रहे।
- इसके लिये बैंकिंग क्षेत्र जो जोखिम लेने के डर से बच रहा है, वह NBFCs को ऋण देकर अर्थव्यवस्था में निरंतर धनराशि का प्रवाह बनाए रखेगा।
- विश्व बैंक समूह अपनी 'अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम' (International Finance Corporation–IFC) शाखा के माध्यम से MSMEs क्षेत्र में तरलता को बनाए रखने के लिये भारत सरकार को निम्नलिखित प्रकार से सहयोग प्रदान करेगा-

1. तरलता को उन्मुक्त करके (Unlocking liquidity)

- इसके तहत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की ओर से MSMEs को दिये जाने वाले ऋणों में अंतर्निहित जोखिम को ऋण गारंटी सहित विभिन्न प्रपत्रों की एक शृंखला के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की जाएगी।

2. NBFCs तथा SFBs को मज़बूत करना (Strengthening NBFCs and SFBs)

- NBFCs तथा 'स्मॉल फाइनेंस बैंक' की वित्त पोषण (फंडिंग) क्षमता बढ़ाने से उन्हें MSMEs की तात्कालिक एवं विविध आवश्यकताओं का पूरा करने में मदद मिलेगी।
- इसमें MSMEs के लिये सरकार की पुनर्वित्त सुविधा द्वारा आवश्यक सहयोग देना भी शामिल होगा।

3. वित्तीय नवाचारों को मज़बूत करना (Enabling financial innovations)

- इसके माध्यम से MSMEs को ऋण देने और भुगतान में फिनटेक एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाना है।

'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' का महत्त्व

- MSMEs क्षेत्र भारत के विकास एवं रोज़गार सृजन के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं जो **COVID-19 के बाद भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाएगा।
- यह कार्यक्रम लक्षित गारंटी/ऋण प्रदान करने में सरकार को आवश्यक सहयोग देगा, जिसके माध्यम से लाभप्रद MSMEs को उधार देने के लिये NBFCs तथा बैंकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- इससे लाभप्रद MSMEs को मौजूदा आर्थिक संकट का सामना करने में मदद मिलेगी।
- यह MSMEs क्षेत्र को समय के साथ आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक सुधारों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

बीआईएस-केयर

चर्चा में क्यों?

27 जुलाई, 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिये भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल एप 'बीआईएस-केयर' (BIS-Care) और www.manakonline.in पर ई-बीआईएस (e-BIS) के तीन पोर्टलों- मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा प्रशिक्षण को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- उपभोक्ता इस एप का उपयोग करके **आईएसआई (Indian Standards Institute–ISI) चिह्नित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रमाणिकता की जाँच** कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (International Events)

उइगर मानवाधिकार नीति अधिनियम, 2020

चर्चा में क्यों?

जून 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने 'उइगर मानवाधिकार विधेयक' को मंजूरी दी। यह अधिनियम ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग करता है जिनके द्वारा चीन में अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह अधिनियम वरिष्ठ चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान करता है जिनमें शिनजियांग कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव आदि शामिल हैं।
- इस अधिनियम में पहली बार चीन के पोलितब्यूरो के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- इन प्रतिबंधों में चीन के शिनजियांग प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव चेन कुआनगुओ (Chen Quanguo) को विशेष तौर पर शामिल किया गया है।
- यह अधिनियम ऐसे समय में लाया गया है जब हाल ही में चीन की संसद के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर मसौदा प्रस्तुत किया गया था जो पहली बार चीन की सरकार को हॉन्गकॉन्ग के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने तथा इस 'विशेष प्रशासनिक क्षेत्र' में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अंगों को संचालित करने की अनुमति देता है।
- चीन के इस मसौदे को प्रस्तुत करने के बाद अमेरिकी संसद द्वारा हॉन्गकॉन्ग में सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन को समर्थन देने वाले कानून को पेश किया गया।

उइगर मुस्लिम

- उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या तकरीबन 40 प्रतिशत है। उइगर नृजातीय रूप से तुर्की के मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं।
- दरअसल, शिनजियांग चीन के भीतर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान सहित आठ देशों के साथ सीमा साझा करता है।
- संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के विशेषज्ञों के अनुसार, कम-से-कम 1 मिलियन उइगर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को शिनजियांग प्रांत के शिविरों में नज़रबंद रखा गया है।
- इस तरह के शिविरों में उइगर समुदाय से संबंधित कलाकारों, लेखकों, पत्रकारों तथा विद्यार्थियों को भारी संख्या में नज़रबंद किया गया है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के संदेह के आधार पर तानाशाही का उपयोग करते हुए उइगर एवं अन्य अल्पसंख्यक समूहों को प्रताड़ित करने के लिये एक 'ऑल आउट' संघर्ष प्रारंभ किया है।

G-7 समूह और भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G-7 को एक 'पुराना समूह' बताते हुए इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को भी शामिल करने की बात कही।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने G-7 के 46वें शिखर सम्मेलन को स्थगित करते हुए कहा कि यह अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- उल्लेखनीय है कि 46वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के कैंप डेविड (Camp David) में 10-12 जून, 2020 के मध्य किया जाना था।
- 45वाँ G-7 शिखर सम्मेलन 24-26 अगस्त, 2019 को फ्राँस के बिआरित्ज़ (Biarritz) में आयोजित किया गया था, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था।
- डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, इस समूह को G-10 अथवा G-11 कहा जाना चाहिये।

G-7 समूह

- G-7 अर्थात् 'ग्रुप ऑफ सेवन' (Group of Seven) फ्राँस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है।

4 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

कुइझोउ-11

चर्चा में क्यों?

जुलाई 2020 में कुइझोउ-11 (Kuaizhou-11) नाम का चीनी रॉकेट उड़ान के दौरान आई खराबी के कारण विफल हो गया जिसके कारण अंतरिक्ष में ले जा रहे दो उपग्रह भी नष्ट हो गए।

प्रमुख बिंदु

- चीनी भाषा में कुइझोउ (Kuaizhou) का अर्थ 'तेज़ जहाज़' होता है। यह एक कम लागत वाला ठोस ईंधन वाहक रॉकेट है।
- इसका वाणिज्यिक लॉन्च 'फर्म एक्सपेस' द्वारा संचालित किया गया था।
- इसे Kz-11 के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 70.8 टन की वहनीय भार क्षमता थी और इसे पृथ्वी की निचली एवं सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
- वाणिज्यिक प्रक्षेपण चीन में एक उभरता हुआ उद्योग है। चीनी सरकार द्वारा वर्ष 2014 में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश के लिये आसान बनाए गए नियमों के बाद अस्तित्व में आई एक्सपेस (Expace), आईस्पेस (Ispace) और लैंडस्पेस (Landspace) जैसी कंपनियाँ अपने पारंपरिक लॉन्च ऑपरेशन के लिये प्रक्रिया क्षमताओं का तीव्र विकास करने पर जोर दे रही है।

स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन डेमो-2

चर्चा में क्यों?

मई 2020 में नासा ने स्पेसएक्स (SpaceX) द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान, क्रू ड्रैगन की सहायता से दो अंतरिक्ष यात्रियों को 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (ISS) भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि स्पेसएक्स किसी मानव अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है।
- स्पेसएक्स द्वारा इस अंतरिक्ष यान में डग हर्ले (Doug Hurley) और बॉब बेनकेन (Bob Behnken) नामक दो अंतरिक्ष यात्रियों को दो चरणों वाले फाल्कन-9 रॉकेट की मदद से 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' के लिये भेजा गया है।
- स्पेसएक्स के कैप्सूल को ISS के साथ 'डॉकिंग प्रक्रिया' को पूरा करने में 28,000 किमी. प्रति घंटे की गति से 19 घंटे का समय लगा।
  - डॉकिंग प्रक्रिया में दो अलग-अलग स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले वाहनों को एक साथ जोड़ा जाता है।
- ISS पहुँचने के साथ ही यात्रा का प्रथम चरण पूरा हो गया है परंतु मिशन को तभी सफल घोषित किया जाएगा जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आएंगे।

क्रू ड्रैगन

- यात्रियों को जिस क्रू कैप्सूल के माध्यम से ले जाया गया है उसे 'क्रू ड्रैगन' (Crew Dragon) नाम दिया गया है।
- यह अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता स्पेसएक्स द्वारा विकसित और निर्मित पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान ड्रैगन-2 का एक हिस्सा है।
- यह मर्करी, जैमिनी, अपोलो और स्पेस शटल प्रोग्राम के बाद मनुष्य को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यान का पाँचवा वर्ग है।

डेमो-1 मिशन

- नासा के डेमो-1 मिशन को स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था। डेमो-1 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च की जाने वाली पहली नॉन-क्रू (मानवरहित) परीक्षण उड़ान थी।
- नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत विकसित प्रणाली की एंड-टू-एंड क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिये डेमो-1 मिशन को डिज़ाइन किया गया था।
- इसे 2 मार्च, 2019 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया था।

रूस पर अमेरिका की निर्भरता

नासा द्वारा वर्ष 2011 में 'अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम' (Space Shuttle Programme) समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद से रूसी 'सोयुज' एकमात्र ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में आवागमन की सुविधा देते हैं। NASA रूस के 'सोयुज स्पेस शटल' कार्यक्रम पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है।

5 भूगोल, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन (Geography, Environment and Disaster Management)

भूगोल

दक्षिण अटलांटिक विसंगति

चर्चा में क्यों?

'यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी' (ESA) के 'स्वॉर्म' (Swarm) उपग्रहों द्वारा प्राप्त आँकड़ों के अध्ययन से दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर 'चुंबकीय विसंगति' का पता चला है। इस 'दक्षिण अटलांटिक विसंगति' (SAA) का विस्तार दक्षिण अमेरिका से दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका तक है।

दक्षिण अटलांटिक विसंगति के बारे में

- SAA अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य पृथ्वी के भू-चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार को संदर्भित करता है।
- यह पृथ्वी के निकटस्थ उस क्षेत्र को इंगित करता है जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कमज़ोर पाया गया है।
- SAA एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी की वान एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी की सतह के 200 किलोमीटर की ऊँचाई तक नज़दीक आ जाती है। वान एलन रेडिएशन बेल्ट ब्राज़ील के तट के पास रेडियोधर्मी कणों को पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र में पकड़ कर रखने के लिये ज़िम्मेदार है।
- इस क्षेत्र में ऊर्जावान कणों का प्रवाह बढ़ने के कारण परिक्रमा कर रहे उपग्रहों को विकिरण के सामान्य से अधिक स्तर तक का सामना करना पड़ता है।
- यह प्रभाव पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुव के कारण होता है।

वान एलन रेडिएशन बेल्ट

- किसी भी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ग्रह के चारों तरफ आवेशित एवं ऊर्जावान कणों की एक 'रेडिएशन बेल्ट' पाई जाती है।
- 'वान एलन रेडिएशन बेल्ट' पृथ्वी के चारों ओर विकिरण बेल्ट को संदर्भित करती है।
- रेडिएशन बेल्ट के मुख्य घटकों का निर्माण सौर पवन तथा कॉस्मिक विकिरणों से होता है।
- पृथ्वी के दो रेडिएशन बेल्ट हैं- एक 'आंतरिक वान एलन रेडिएशन बेल्ट' और दूसरा 'बाहरी रेडिएशन बेल्ट'।
- आंतरिक रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी की सतह से 1000 किमी. से 6000 किमी. की ऊँचाई तक विस्तृत है। आंतरिक बेल्ट में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों का संयोजन होता है।
- बाह्य रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी सतह से 15,000 किमी. से 25,000 किमी. तक विस्तृत है। बाह्य विकिरण बेल्ट में मुख्यत: ऊर्जावान तथा आवेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।

भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात

चर्चा में क्यों?

मई और जून माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तथा महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग ने तटीय क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। निसर्ग चक्रवात का निर्माण दक्षिण-पूर्व और पूर्व-मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप के कम दबाव वाले क्षेत्र में हुआ।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं जिनका व्यास सामान्य रूप से 80 से 300 किलोमीटर तक होता है।
- ये चक्रवात साधारण से प्रचंड गति में आगे बढ़ते हैं। क्षीण चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटे तथा हरिकेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज़ चलते हैं।
- सागरों के ऊपर इनकी गति अधिक तीव्र होती है, जबकि स्थलों पर पहुँचते-पहुँचते ये क्षीण हो जाते हैं। इसी कारण ये केवल महाद्वीपों के तटीय भागों को ही अधिक प्रभावित कर पाते हैं।
- चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण हवाएँ तेज़ी से केंद्र की ओर झपटती हैं और तूफानी गति धारण कर लेती हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात साधारण तौर पर व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं।

निर्माण के लिये अनुकूल दशाएँ

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति विषुवत रेखा के दोनों ओर महासागरों के ऊपर होती हैं।
- इन चक्रवातों के निर्माण के लिये समुद्री सतह का तापमान सामान्यत: 26-27°C होना आवश्यक है।
- वायुमंडल में लगभग 5000 मीटर की ऊँचाई तक उच्च सापेक्षिक आर्द्रता के साथ-साथ वायुमंडलीय अस्थिरता विद्यमान होनी चाहिये, जिससे ऊर्ध्वाधर कपासी वर्षा मेघ का निर्माण हो सके।
- भूमध्य रेखा पर कोरिओलिस बल शून्य होने के कारण भूमध्य रेखा पर चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। 5° अक्षांश पर कोरिओलिस बल चक्रवात निर्माण के लिये पर्याप्त एवं महत्त्वपूर्ण है। लगभग 65 प्रतिशत चक्रवाती गतिविधियाँ 10° और 20° अक्षांश के बीच होती है।

6

सुरक्षा (Security)

खालिस्तान आंदोलन और ऑपरेशन ब्लू स्टार

चर्चा में क्यों?

जून 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं वर्षगाँठ पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि यदि सरकार सिखों के लिये एक पृथक राज्य के रूप में खालिस्तान का प्रस्ताव पेश करती है, तो सिख समुदाय इसे स्वीकार करेगा।

खालिस्तान आंदोलन

- खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है, जो पंजाब क्षेत्र में 'खालिस्तान' (खालसा की भूमि) नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिये एक अलग मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है।
- 'खालिस्तान' के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग 1980 के दशक में और भी ज़ोर पड़ने लगी और मांग तेज़ होने के साथ इसका नाम 'खालिस्तान आंदोलन' पड़ा।
- इसी बीच एक चरमपंथी सिख नेता के रूप में जरनैल सिंह भिंडरावाला की लोकप्रियता भी काफी बढ़ने लगी। माना जाता है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले ने ही खालिस्तान को चरमपंथी आंदोलन का रूप दिया था।

ऑपरेशन ब्लूस्टार

- 'खालिस्तान' आंदोलन के एक हिंसक रूप धारण करने के बाद पंजाब में आतंकी घटनाओं में काफी तेज़ी आने लगी। समय के साथ तेज़ होती इस प्रकार की घटनाएँ और जरनैल सिंह भिंडरावाले की बढ़ती लोकप्रियता तत्कालीन सरकार के लिये एक प्रमुख चुनौती बन गई।
- स्थिति के मद्देनज़र तत्कालीन सरकार ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के कार्यान्वयन का निर्णय लिया और 1-3 जून, 1984 के बीच पंजाब में सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया। साथ ही स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई को भी रोक दिया गया।
- 6 जून, 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला तथा उसके समर्थक मारे गए।
- इस ऑपरेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के कुल 83 जवानों की मौत हुई और 249 जवान घायल हुए। वहीं इस बीच 493 से अधिक आतंकी और आम लोगों की भी मौत हुई।

खालिस्तान आंदोलन का मौजूदा स्वरूप

- वर्तमान में खालिस्तान आंदोलन भारत में एक निष्क्रिय आंदोलन है और पंजाब के शहरी तथा ग्रामीण आबादी में इसके प्रति कुछ खास आकर्षण नहीं दिखाई देता है।
- हालाँकि, भारत के बाहर रहने वाले सिखों में इस आंदोलन का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है और समय-समय पर इस आंदोलन के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं।
- कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि भारत में अशांति और असंतोष फैलाया जा सके।

चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

चर्चा में क्यों?

जून में 'गृह मंत्रालय' (MHA) ने चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (BADP) के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किये।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' हेतु ₹784 करोड़ आवंटित किये गए हैं।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इस धनराशि को वितरित किया गया है।
- भारत और चीन के बीच हालिया सीमा विवादों के मद्देनज़र सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिये बुनियादी ढाँचे का निर्माण एक रणनीतिक कदम है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

- सातवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1985-90) के दौरान पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की शुरुआत की गई थी।
- वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 16 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 111 सीमावर्ती ज़िलों के 396 सीमा खंड शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीकी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक खुशहाली और उन्हें कनेक्टिविटी संबंधी सुविधाएँ, स्वच्छ पेयजल, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सुविधाएँ सुलभ कराना है।

7 रिपोर्ट एवं सूचकांक (Reports and Indices)

प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

चर्चा में क्यों?

अप्रैल 2020 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा जारी 180 देशों के 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' 2020 में भारत 142वें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था।
- इस सूचकांक में पत्रकारों के लिये उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है।
- यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढाँचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है।
- 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020' में पहले स्थान पर नॉर्वे है, जो कि वर्ष 2019 में भी पहले स्थान पर था। इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान फिनलैंड को और तीसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है।
- इस सूचकांक में 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, जो कि बीते वर्ष 179वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को 67वाँ स्थान, म्याँमार को 139वाँ स्थान, पाकिस्तान को 145वाँ स्थान, नेपाल को 112वाँ स्थान, अफगानिस्तान को 122वाँ स्थान, बांग्लादेश को 151वाँ स्थान और चीन को 177वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान (International Press Institute-IPI) ने भी भारत में हालिया घटनाओं के परिदृश्य में अधिकारियों द्वारा कानून का दुरुपयोग, पत्रकारों को डराने-धमकाने और प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी निंदा की है।

भारतीय परिदृश्य

- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा एकत्रित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, जबकि वर्ष 2018 में देश में कुल 6 पत्रकारों की हत्या हुई है।
- रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारत में आपराधिक धाराओं को उन लोगों खासकर पत्रकारों के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है, जो अधिकारियों की आलोचना करते रहे हैं। उदाहरण के लिये बीते दिनों देश में पत्रकारों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A (राजद्रोह) के प्रयोग के कई मामले सामने आए हैं।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है, जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को रिपोर्टर्स संस फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है।
- इसका मुख्यालय पेरिस में है।

'लॉस्ट एट होम' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

'संयुक्त राष्ट्र बाल कोष' (UNICEF) द्वारा 5 मई, 2020 को प्रकाशित 'लॉस्ट एट होम' (Lost at Home) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में लगभग 46 मिलियन लोगों का अपने देश की सीमाओं के भीतर आंतरिक विस्थापन हुआ है।

आंतरिक विस्थापन: प्रवृतियाँ एवं प्रतिरूप

- 2019 के अंत में संघर्ष और हिंसा के परिणामस्वरूप लगभग 45.7 मिलियन लोग जबरदस्ती विस्थापन की स्थिति में रह रहे थे। विस्थापित कुल जनसंख्या में 19 मिलियन बच्चे थे जो कुल विस्थापितों का लगभग 42% है।
- आंतरिक रूप से विस्थापित लोग अधिकांशत: दो क्षेत्रों- मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका में संकेंद्रित हैं। मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में 2019 के अंत में संघर्ष और हिंसा के परिणामस्वरूप 12 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित दर्ज किये गए। इनमें से लगभग सभी तीन देशों सीरिया (6.5 मिलियन), यमन (3.6 मिलियन) और इराक (1.6 मिलियन) में रह रहे थे। उप-सहारा अफ्रीका में संघर्ष और हिंसा के कारण आंतरिक विस्थापितों की संख्या लगभग 19 मिलियन है।
- 2019 में लगभग 33 मिलियन नए लोग आंतरिक रूप से विस्थापित दर्ज किये गए हैं। इनमें से प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 25 मिलियन और संघर्ष तथा हिंसा के परिणामस्वरूप 8.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। संघर्ष और हिंसा की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नए विस्थापन अधिक हुए है।

8 सरकारी योजनाएँ (Government Schemes)

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान

चर्चा में क्यों?

COVID-19 महामारी के चलते प्रवासी मज़दूरों के समक्ष उत्पन्न रोज़गार की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून, 2020 को 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया ज़िले के ग्राम तेलिहार से शुरू किया गया। यह 125 दिनों का अभियान होगा, जिसे मिशन मोड में संचालित किया जाएगा।
- इस अभियान में छः राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा) को शामिल किया गया है।
- छः ज़िलों के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 ज़िलों को इस अभियान के लिये चुना गया है, जिसमें 27 आकांक्षी ज़िले भी शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम में शामिल छः राज्यों के 116 ज़िलों के गाँव कॉमन सर्विस सेंटर तथा 'कृषि विज्ञान केंद्रों' के माध्यम से शामिल होंगे, जो कोरोना के कारण लागू शारीरिक दूरी के मानदंडों को भी ध्यान में रखेंगे।
- यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का समन्वित प्रयास है, जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़क संगठन, दूरसंचार तथा कृषि मंत्रालय शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

चर्चा में क्यों?

जून में आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में गली-मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविड-19 की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर से चालू करने में मदद मिलेगी।

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारी अथवा रेहड़ी-पटरी विक्रेता (Street Vendor) ₹10,000 तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
- ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी।
- कर्ज़ का समय पर या उससे पहले भुगतान करने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज़ लेने वाले के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
- पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा।
- यदि कर्ज़दार किस्तों का भुगतान समय पर या समय से पहले करता है तो मंत्रालय उनका विश्वसनीयता सूचकांक तैयार करेगा जिसके आधार पर वह ₹20,000 या उससे अधिक का सावधि ऋण हासिल करने का पात्र होगा।
- इस योजना के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी।
- इस योजना के लिये सरकार द्वारा ₹5,000 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है।
- इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक है।
- इस योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
- इस तरह के ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह बैंकों द्वारा प्रदान किये जाएंगे।

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2020 से 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना में तीन और राज्य (ओडिशा, सिक्किम, मिज़ोरम) शामिल हो गए।

क्रियान्वयन एजेंसी

इस योजना का क्रियान्वयन 'केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' द्वारा किया जा रहा है।

9 कला एवं संस्कृति (Art and Culture)

कोणार्क सूर्य मंदिर

चर्चा में क्यों?

20 मई, 2020 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत 10 मेगावॉट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और विभिन्न ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों, जैसे- सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क, बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ-ग्रिड सौर संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (OREDA) द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा।

ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली

- ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली किसी भी ग्रिड से जुड़ी नहीं होती है। इस प्रणाली के साथ एक बैटरी जुड़ी होती है जो सौर उर्जा से उत्पादित विद्युत को संचित करती है।
- दरअसल 'ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली' में सौर पैनल, बैटरी, चार्ज नियंत्रक, ग्रिड बॉक्स, इनवर्टर इत्यादि होते हैं।
- यह सौर प्रणाली उन क्षेत्रों के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है जहाँ पॉवर ग्रिड की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कोणार्क सूर्य मंदिर

- कोणार्क शब्द, 'कोण' और 'अर्क' शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी के उत्तर पूर्वी किनारे पर समुद्र तट के करीब निर्मित है। इस मंदिर के तीन हिस्से हैं- नृत्यमंदिर, जगमोहन, गर्भगृह।
- कोणार्क ओडिशा की प्राचीन वास्तुशैली का विशिष्ट मंदिर है, जिसमें मंदिर में मुख्य मंदिर, महामण्डप, रंगशाला व सटा भोगमण्डप होते थे। इनमें से ज़्यादातर में जगमोहन व मुख्य मंदिर एक साथ जुड़े होते थे। कोणार्क मंदिर में थोड़ी भिन्नता है। यहाँ पर जगमोहन व मुख्य मंदिर सटे थे। पूर्व में स्थित प्रवेश द्वार के बाद नाट्यमण्डप है।
- कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था।
- मंदिर का महामण्डप बेहद आकर्षक है, जिसका शीर्ष पिरामिड के आकार का है। इसमें विभिन्न स्तरों पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि आदि नक्षत्रों की प्रतिमाएँ हैं। इसके ऊपर विशाल आमलक है। समीप ही सूर्य की पत्नी मायादेवी व वैष्णव मंदिर खंडित अवस्था में है। समीप में भोगमण्डप था। एक नवग्रह मंदिर भी यहाँ पर है।
- ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को (UNESCO) ने वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) इस मंदिर का संरक्षक है।

पुरंदर दास : कर्नाटक संगीत के पिता

चर्चा में क्यों?

'पुरातत्त्व, विरासत एवं संग्रहालय विभाग' ने हाल ही में कर्नाटक के तीर्थहल्ली में अनुसंधान कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। इस शोध का उद्देश्य पुरंदर दास, जिन्हें 'कर्नाटक संगीत के पिता' के रूप में सम्मानित किया गया था, के जन्मस्थान के बारे में स्पष्ट पुरातात्त्विक साक्ष्य का पता लगाना है।

पुरंदर दास

- कर्नाटक संगीत में इनके महत्त्वपूर्ण योगदान के सम्मान में इन्हें व्यापक रूप से 'संगीत पितामह' के रूप में जाना जाता है। वे भगवान कृष्ण के महान भक्त, वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक थे।
- वह द्वैत दार्शनिक संत व्यासतीर्थ के शिष्य थे और कनकदास के समकालीन थे। उनके गुरु व्यासतीर्थ ने अपने एक गीत 'दसरेंदर पुरंदर दारासराय' में पुरंदर दास की महिमा का बखान किया है।
- वह एक संगीतकार, गायक और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत (कर्नाटक संगीत) के मुख्य संस्थापकों में से एक थे।
- हरिदास परंपरा (भगवान हरि या भगवान कृष्ण का सेवक) की शुरुआत करने से पहले पुरंदर दास एक अमीर व्यापारी थे और उन्हें 'श्रीनिवास नायक' कहा जाता था।
- इतिहासकार बताते हैं कि पुरंदर दास का जन्म मलनाड में हुआ था और उनको मिली 'नायक' की उपाधि का श्रेय विजयनगर साम्राज्य को जाता है क्योंकि विजयनगर शासन के दौरान 'नायक' की उपाधि मलनाड के धनी व्यापारियों सहित स्थानीय प्रभावशाली लोगों को दी गई थी।

10 खेल घटनाक्रम (Sports Events)

इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज टैस्ट शृंखला

चर्चा में क्यों?

8 जुलाई से 28 जुलाई, 2020 के बीच इंग्लैंड व वेस्ट इंडीज के बीच तीन टैस्ट मैच की शृंखला (विज़्डन ट्रॉफी) संपन्न हुई। इसे इंग्लैंड ने 2-1 से जीत लिया।

मुख्य बिंदु

- कोरोना महामारी के चलते चार माह क्रिकेट न खेले जाने के बाद यह पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शृंखला थी।
- कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उद्देश्य से इस शृंखला से क्रिकेट में अनेक नए नियम लागू किये गए।
- शृंखला के तीनों मैच दर्शकों की अनुपस्थिति में खिलाड़ियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन सुनिश्चित करते हुए साउथंपटन व मैनचेस्टर में Bio-secure Bubbles में खेले गए।
- शृंखला का पहला मैच वेस्ट इंडीज द्वारा जीते जाने के बाद शेष दो मैच इंग्लैंड ने जीते और शृंखला पर कब्जा किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को 'प्लेयर ऑफ द मैच' व स्टुअर्ट ब्रॉड को ही वेस्ट इंडीज के रॉस्टन चेज़ के साथ संयुक्त रूप से 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार दिया गया।

आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप, 2020

- सातवें आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप, जो आस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, के फाइनल में आस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर प्रतियोगिता जीत ली।
- उल्लेखनीय है कि 'प्लेयर ऑफ द सीरीज़' ऑस्ट्रेलिया की बैथ मूनी (आस्ट्रेलिया) रहीं। बैथ मूनी ने इस विश्व कप में सर्वाधिक रन (259) एवं मेगन शट ने सर्वाधिक विकेट (13) लिये।
- वहीं सैफाली वर्मा भारत के लिये सबसे कम उम्र की (16 साल) विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी रहीं।

अंडर-17 महिला विश्व कप

- विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने भारत में पहली बार 2021 में अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन करने की मंजूरी दे दी है।
- उल्लेखनीय है कि पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन 2020 में किया जाना था, परंतु कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित किया गया।
- भारत ने फ्राँस को पीछे छोड़ते हुए मेज़बानी का अधिकार हासिल किया।
- यह अंडर-17 महिला विश्व कप इसका सातवाँ संस्करण होगा। गौरतलब है कि यह भारत में फीफा का दूसरा आयोजन होगा। इससे पहले 2017 में भारत ने पहली बार अंडर-17 पुरुष विश्व कप की मेज़बानी की थी।

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप-2019

चर्चा में क्यों?

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के 12वें संस्करण में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल मैच में 14 जुलाई को इंग्लैंड ने न्यूज़ीलैंड को हराकर पहली बार विजेता बनने का गौरव हासिल किया। यह पाँचवां अवसर था जब यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया।

मुख्य बिंदु

- इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला गया फाइनल मैच पहले टाई हुआ क्योंकि दोनों ही टीमों ने निर्धारित 50 ओवरों में 241 रन बनाए।
- इसके बाद मैच में सुपर ओवर खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाज़ी की और एक ओवर में 15 रन बनाए।
- न्यूज़ीलैंड ने भी सुपर ओवर में 15 रन बनाए। इस प्रकार सुपर ओवर भी टाई हो गया।
- लेकिन ICC के तत्कालीन नियमों के अनुसार इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया, क्योंकि उसने अपनी पारी के दौरान ज़्यादा चौके-छक्के मारे थे।
- इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच तथा न्यूज़ीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी

- 1 दिसंबर, 2019 को लालाभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, सूरत में खेले गए राष्ट्रीय T-20 टूर्नामेंट के फाइनल में तमिलनाडु को 1 रन से हराकर कर्नाटक ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी जीती है।
- ध्यातव्य है कि कर्नाटक छठी टीम है जिसने तीनों प्रारूपों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2008-09 में हुई थी।

एफआईएच महिला सीरीज़

- भारत की महिला हॉकी टीम ने हिरोशिमा हॉकी स्टेडियम में जापान को 3-1 से हराकर एफआईएच महिला सीरीज़ प्रतियोगिता जीत ली।
- इससे पहले इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में चिली को 4-2 से हराने के साथ ही भारत ने वर्ष 2020 में टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिये क्वॉलिफायर के अंतिम चरण हेतु

11 विविध (Miscellaneous)

चर्चित व्यक्ति

नियुक्ति

अशोक लवासा

- जुलाई 2020 में भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक (ADB) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अशोक लवासा वर्तमान उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
- उन्हें 3 वर्षों के लिये ADB के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।
- ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।

डॉ. हर्षवर्धन

मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉ. हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉ. हिरोकी नकातानी का स्थान लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति ज़िम्मेदार संयुक्त राष्ट्र (UN) की विशिष्ट संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का मुख्य कार्य विश्व स्वास्थ्य सभा की नीतियों को प्रभावी बनाने हेतु सलाह देना और सभा के कार्य को सुविधाजनक बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में की गई थी।

वी. विद्यावती

वरिष्ठ IAS अधिकारी वी. विद्यावती को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश पर की गई है। वी. विद्यावती 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की IAS अधिकारी हैं। संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण हेतु एक प्रमुख संगठन है। ASI का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों एवं अवशेषों का रख-रखाव करना है। साथ ही यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को भी विनियमित करता है।

प्रवीण राव

अप्रैल 2020 में IT उद्योग की संस्था नासकॉम (NASSCOM) ने इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) प्रवीण राय को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे WNS ग्लोबल सर्विसेज़ के CEO केशव मुरुगेश का स्थान लेंगे। इसके अलावा एसेंचर (Accenture) की भारत में अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा मेनन को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रवीण राय और रेखा मेनन की नियुक्तियों की घोषणा नासकॉम की कार्यकारी परिषद की बैठक में की गई, जिसका आयोजन COVID-19 संकट के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। ध्यातव्य है कि यह समय भारतीय IT उद्योग समेत तमाम उद्योगों के लिये एक चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि भारत एक संकटपूर्ण स्थिति का मुकाबला कर रहा है।

विश्वनाथन आनंद

अप्रैल 2020 में विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को 'वर्ल्ड वाइड फंड- इंडिया' (World Wide Fund-India) के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया। इस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1976 में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत देश के युवाओं, स्कूली बच्चों और नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समस्या हल करने में सक्षम, महत्त्वपूर्ण विचारकों और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों का निर्माण करना है। वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) का गठन

दिवस/सम्मेलन

तिथि	दिवस	मुख्य विषय
3-7 जनवरी, 2020	107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस	(कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूरू); थीम: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : ग्रामीण विकास।
6-10 जनवरी, 2020 (पुणे)	एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन	–
9 जनवरी	प्रवासी भारतीय दिवस	–
10 जनवरी, 2020	विश्व हिंदी दिवस	–
12 जनवरी, 2020	राष्ट्रीय युवा दिवस	–
13 जनवरी, 2020	विश्व रेडियो दिवस	Radio and diversity
24 जनवरी, 2020	राष्ट्रीय बालिका दिवस	–
24 जनवरी, 2020	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस	Learning for people, planet, property, and peace.
25 जनवरी, 2020	राष्ट्रीय मतदाता दिवस	मजबूत लोकतंत्र के लिये चुनावी साक्षरता
2 फरवरी, 2020	विश्व आर्द्रभूमि दिवस	आर्द्रभूमियाँ एवं जैव विविधता
4 फरवरी, 2020	विश्व कैंसर दिवस	'I am and I will'
5-8 फरवरी, 2020 (लखनऊ)	डेफएक्सपो 2020	थीम: इंडिया : द इमर्जिंग डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हब (India : The Emerging Defence Manufacturing Hub)
20 फरवरी	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	थीम: विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएँ।
21 फरवरी, 2020	अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस	Languages without bordery
28 फरवरी, 2020	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	विज्ञान में महिलाएँ
3 मार्च, 2020	विश्व वन्यजीव दिवस	'Sustaining all life on earth'
5-7 मार्च, 2020 (कोलकाता)	नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	–
8 मार्च, 2020	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	I am Generation equality : Reading women's Rights'
13 मार्च, 2020	विश्व वृक्क दिवस	–
13 मार्च, 2020	वर्ल्ड स्लीप डे	Better sleep, Better life, Better planet
14 मार्च	पाई (π) डे	–
15 मार्च, 2020	विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस	'The Sustainble consumer'
20 मार्च, 2020	अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस	'Happiness for all, together'
21 मार्च, 2020	अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस	वन एवं जैव विविधता
22 मार्च, 2020	विश्व जल दिवस	जल एवं जलवायु परिवर्तन
23 मार्च, 2020	विश्व मौसम विज्ञान दिवस	जलवायु एवं जल
24 मार्च, 2020	विश्व क्षयरोग दिवस	'It's Time'
28 मार्च, 2020	अर्थ ऑवर	–
2 अप्रैल, 2020	विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस	'The transition to adulthood'
4 अप्रैल, 2020	अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस	–
7 अप्रैल, 2020	विश्व स्वास्थ्य दिवस	'Support Nurses and Midwives'
12 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस	
26 अप्रैल	विश्व बौद्धिक संपदा दिवस	थीम: इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर।
11 मई, 2020	29वाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	मुख्य फोकस: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को रिबूट करना।
17 मई, 2020	विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस	थीम: Connect 2030 : ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस

21 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2015 में भारत ने मिलान (इटली) में खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) के अंतर-सरकारी समूह की बैठक में 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। परिणामत: 15 दिसंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप घोषित किया। वर्तमान में विश्व के 35 से अधिक देशों में चाय का उत्पादन होता है और विश्व भर में छोटे किसानों सहित इस क्षेत्र में 13 मिलियन लोग संबद्ध हैं। देश में 100 से अधिक किस्मों की खपत के साथ भारत चाय के शीर्ष चार उत्पादकों में शामिल है। चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका के लगभग 90 लाख किसान आय के लिये चाय उत्पादन पर निर्भर हैं।

दृष्टि The Vision

drishti

Think IAS Think Drishti

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स
(IAS Prelims Online Course)

प्रिय विद्यार्थियो,

संसाधन की कमी अक्सर हमारी उड़ान को सीमित कर देती है। हममें आगे बढ़ने की तड़प तो खूब होती है किंतु उसे साकार करने वाले साधनों का अभाव हमें मायूस कर देता है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों से आप जैसे हज़ारों विद्यार्थियों ने हमें इस आशय के संदेश भेजे कि वे सिविल सेवा में जाने की इच्छा तो रखते हैं किंतु इसकी तैयारी के लिये दिल्ली में रहने का भारी-भरकम खर्च उठा पाना उनके लिये संभव नहीं है। साथ ही आपने हमसे यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिसमें आप घर-बैठे दृष्टि की कक्षा कार्यक्रम जैसी गुणवत्तापरक क्लास कर पाएँ। आपके इन्हीं निवेदनों को ध्यान में रखते हुए हम अपना पहला 'पेन ड्राइव कोर्स' जारी कर रहे हैं जो आई.ए.एस. प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। इसमें आप सामान्य अध्ययन तथा सीसैट के कोर्स ले सकते हैं। लगभग 2 वर्षों की कठोर मेहनत से तैयार हुआ यह वीडियो कोर्स गुणवत्ता में अच्छे से अच्छे क्लासरूम प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। हमें विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम IAS मुख्य परीक्षा और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं के लिये भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे।

एडमिशन प्रारंभ

विद्यार्थियों की भारी मांग को देखते हुए ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स पर 20% की विशेष छूट अब शुरुआती 1000 विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध

मोड : पेन ड्राइव

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com पर FAQs पेज देखें

IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
2. 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीज़न भी कर सकें।
4. कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
5. हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
6. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
7. प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निःशुल्क)।
8. ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ (25+5 टेस्ट) की निःशुल्क सुविधा।
9. क्विक बुक सीरीज़ की 8 पुस्तकें निःशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटीरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
10. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) करते हैं तो आपकी ऑनलाइन कोर्स की फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।

जानकारी के लिये कॉल करें- 9319290700, 9319290701, 9319290702 या सिर्फ मिस्ड कॉल करें- 8010600300

दिल्ली शाखा का पता : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज शाखा का पता : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज
Ph.: 8448485517, 8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

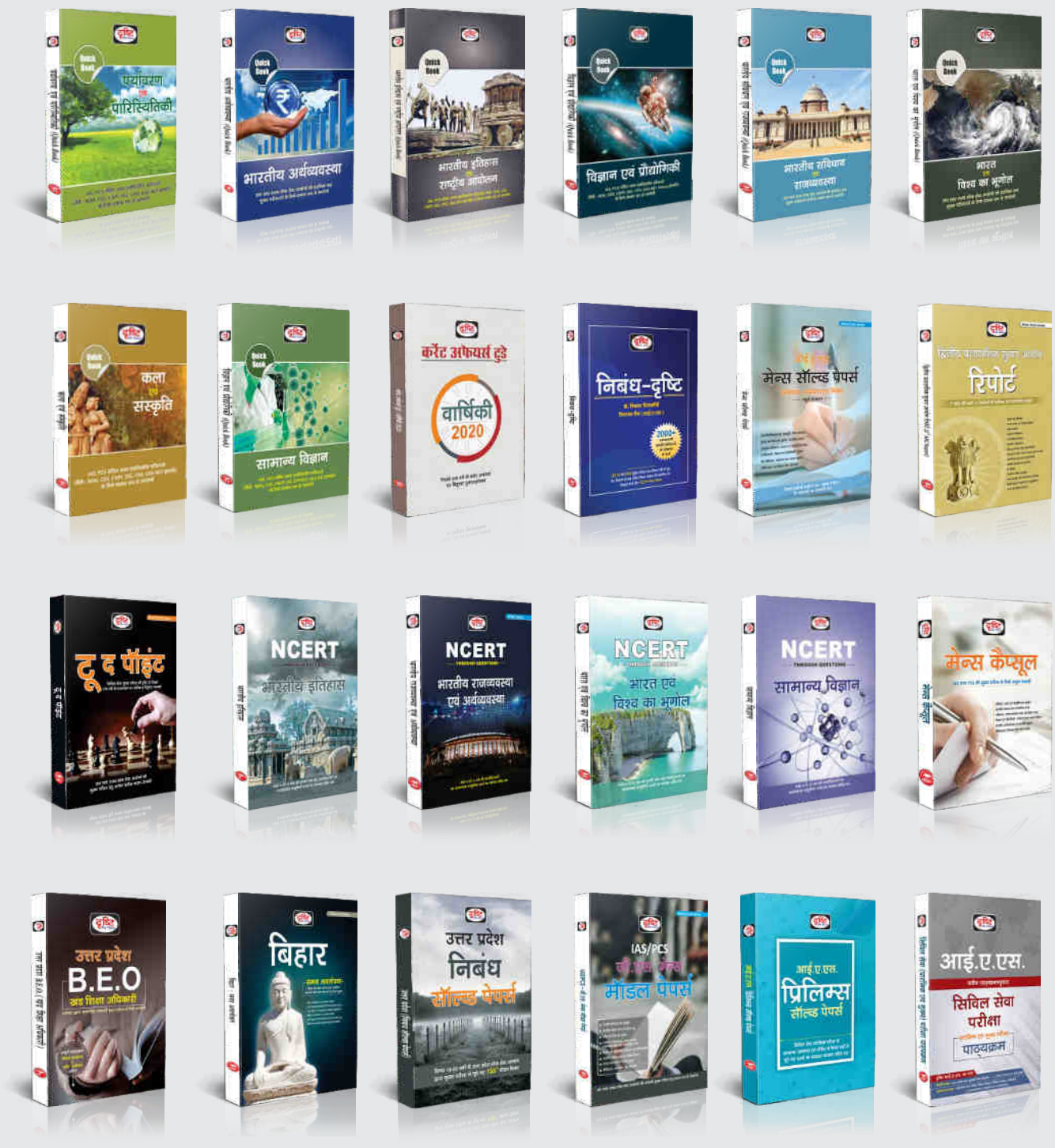

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-945474-8-8

मूल्य : ₹ 150